



The Sixty-Year-Old Jet That Slipped ...

The irony became impossible to ignore. The "museum jet" survived long enough to strike its target. America's advanced fighters did not

International Day of University Sport

The Education of the Children of Clovis

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

कनाटक में अमित शाह का स्वास्थ्य बिगड़ा

कांग्रेस से अलग तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है डीएमके

डीएमके नेता कनिमोई ने विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ मीटिंग कीं

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का सूपड़ा साफ। छात्र संघ अध्यक्ष सहित तीन पदों पर एबीवीपी और एक पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की

–डॉ. सतीश मिश्रा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 19 सितंबर कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए, आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 में चार में से तीन पदों पर जीत हासिल कर ली, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। एनएसयूआई सभी पदों पर हार गई।
कड़े मुकाबले वाले चुनाव में एबीवीपी के यश डबास 24,576 वोट हासिल कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने एनएसयूआई उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को हराया, जिन्हें 22,523 वोट मिले।
एबीवीपी की रिया चावड़ी ने एनएसयूआई की अपनी प्रतिद्वंदी नम्रता चौधरी को हराकर सचिव पद

- अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के यश डबास ने 24,576 वोट लिए और एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा (22,523 वोट) को हराया। सचिव तथा संयुक्त सचिव पद भी एबीवीपी के खाते में गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शोकीन ने एबीवीपी और एनएसयूआई को हराया है।
- यश डबास ने अपनी जीत का श्रेय संघ की सामूहिक ताकत को दिया और कहा कि यह सद्भाव तथा देश प्रेम की जीत है।

हासिल किया।
संयुक्त सचिव पद के लिए, एबीवीपी, एनएसयूआई और एससीबी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। एबीवीपी के लक्ष्यराज सिंह विजयी रहे।
निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने एबीवीपी के अपने प्रतिद्वंदी

इशु मौर्य को हराकर उपाध्यक्ष पद जीत लिया। एनएसयूआई उम्मीदवार वीर चतरथ काफी अंतर से पिछड़ कर तीसरे स्थान पर रहे।
अध्यक्ष पद जीतने वाले यश डबास ने कहा कि यह सद्भाव, देशभक्ति और संघ की सामूहिक ताकत की जीत है।

उन्होंने कहा, “पीयू से लेकर डीयू तक के संस्थानों के छात्रों ने हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। कैपस से एनएसयूआई का पूरी तरह सफाया हो गया है, वह 4-0 से हार गई।”
डबास ने कहा कि हाल में सत्य निकेतन पीजी के ढहने की घटना के मद्देनजर उनका पैनाल हर पीजी और हॉस्टल का सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिक चिंता यह सुनिश्चित करना होगी कि हर पीजी और हॉस्टल का सुरक्षा ऑडिट किया जाए। हम सभी ने सत्य निकेतन में हुई दुर्घटना देखी है, हम नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ हो और यही हमारी पहली प्राथमिकता होगी, हर कॉलेज, हॉस्टल और पीजी का सुरक्षा ऑडिट कराना।

- डॉक्टरों की सलाह पर कुछ घंटे आराम के बाद वे दिल्ली रवाना हो सकते हैं।

करने की सलाह दी है। इस बीच धारवाड़ के जिलाधिकारी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश पाटील ने अमित शाह के ठहरने वाले निजी होटल का दौरा किया।
‘डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, आराम करने के बाद अमित शाह के सीधे दिल्ली रवाना होने की संभावना है। तबीयत खराब होने के कारण शनिवार को उनके निर्धारित कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए।
अमित शाह शुक्रवार देर रात विशेष विमान से दिल्ली से हुबली हवाई अड्डे पहुंचे थे। इसके बाद वे एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। शनिवार को अमित शाह को केएलई संस्था के नवनिर्मित (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

- श्रीनंद झा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 19 सितम्बर कांग्रेस को बाहर रखते हुए, तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाशने के प्रयासों को उस समय और बल मिला, जब द्रमुक नेता तथा लोकसभा सांसद कनिमोई करुणानिधि ने प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं के साथ एक के बाद एक बैठकें कीं।
कनिमोई ने पिछले सप्ताह मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास “मातोश्री” पर मुलाकात की। बैठक में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद भी मौजूद थे। बातचीत में परिसीमन विधेयक को हराते, “इंडिया” ब्लॉक के भविष्य और विपक्ष में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी, लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के साथ अलग-अलग
- डीएमके सांसद कनिमोई, शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार और सुप्रिया सुले तथा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के साथ मीटिंग्स कर चुकी हैं।
- मई 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बाद से ही डीएमके और कांग्रेस के रिश्ते में खटास आ गई है।

बातचीत की। गुरुवार को कनिमोई ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी से उनके कालीघाट स्थित आवास पर एक घंटे से अधिक समय तक मीटिंग की। हालांकि इन दलों का कहना है कि मुलाकातों में क्षेत्रीय आवाजों को मजबूत करने तथा परिसीमन और जातीय जनगणना जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन मुलाकातों के इस सिलसिले ने क्षेत्रीय

ताकतों के एक व्यापक मंच की संभावना से संबंधित अटकलों को हवा दी है।
यह संपर्क डीएमके-कांग्रेस संबंधों में आई तेज गिरावट की पृष्ठभूमि में हो रहा है। मई 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस डीएमके के नेतृत्व वाले “सेक्यूलर प्रोग्रेसिव अलायंस” से बाहर हो गई थी और टीवीके सरकार को समर्थन दे दिया (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

निकाय चुनाव में भजनलाल की रणनीति पर खुलकर अमल हुआ

मुख्यमंत्री ने चुनाव का मोर्चा खुद संभाला, बड़े नेताओं को संभागवार जिम्मेदारी देकर नियमित फीडबैक लिया

जयपुर, 19 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मजबूत रणनीति और नेतृत्व से प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में कमल खिला। मुख्यमंत्री की अगुवाई और मार्गदर्शन में मिशन मोड पर यह चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री, गुहमन्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने राजस्थान में भाजपा के दमदार प्रदर्शन और जीत पर मुख्यमंत्री की रणनीति को सराहा और उनकी प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में टिकट वितरण में पार्टी और संगठन को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने खुद चुनाव का मोर्चा संभाला तथा बड़े नेताओं को संभागवार जिम्मेदारी दी और प्रतिदिन फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं चुनावी मैदान में उतरकर 10 नगर

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं मैदान में उतर कर 10 नगर निगमों में रोड शो किए। परिणाम आने के बाद भाजपा पार्षदों को एकजुट रखा तथा निर्दलियों को साथ कर पार्टी को शानदार जीत दिलाई।

निगमों में रोड शो किए। निकाय चुनाव के परिणामों के बाद सभी पार्षदों को एकजुट रखा और निर्दलीयों को साधा। मुख्यमंत्री की इस रणनीति से कांग्रेस की जीत के दावे और उनकी पिक्चर फ्लॉप शो साबित हुई। उनकी अगुवाई में भरतपुर और डीग जिले की 90 प्रतिशत नगरपालिकाओं में भाजपा ने अपना बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की और भरतपुर नगर निगम में भी निर्विरोध कमल खिलाया। जयपुर में लगातार सातवीं बार नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपना निर्विवाद नेतृत्व साबित किया है।

राजस्थान में इस बार सभी 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद सहित, 252 नगर पालिकाओं में चुनाव एक साथ हुए हैं। इन निकायों में दमदार जीत सरकार के ढाई साल के काम पर जनता की मोहर है। इससे पहले, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए चुनाव में पिछले साल 7 में से 5 उपचुनाव में भाजपा जीती थी। जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रोड शो ने राजधानी की जीत में अहम भूमिका निभाई। परकोटे से ही भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी सुनील कोठारी जीते हैं। मुख्यमंत्री ने रोड शो में परकोटे के लोगों को स्पष्ट संदेश (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

आरएसएस के खिलाफ बयान नहीं देने का आश्वासन नहीं दिया खड़गे ने

नई दिल्ली, 19 सितंबर। राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट में शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान नहीं देने का लिखित वचन देने से इनकार कर दिया। स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार ने मामले

- शिकायतकर्ता ने अदालत से कहा था कि खड़गे लिखित आश्वासन दें तो वे याचिका वापस ले सकते हैं।

की अगली सुनवाई 28 सितंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता रवीन्द्र कुमार गुप्ता की ओर से कहा गया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं, बशर्ते मल्लिकार्जुन खड़गे इस आशय का लिखित वचन दें कि वे आरएसएस के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। तब मल्लिकार्जुन खरो की ओर (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने रूस से तेल लेने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कानून पर साइन किए

इस कानून के दायरे में आने वाले देशों में भारत और चीन प्रमुख हैं

- जाल खंबाता –
– राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो –
नई दिल्ली, 19 सितंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया है। इससे रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है और भारत तथा चीन पर भी खतरा मंडराने लगा है।
ट्रंप को इस मंजूरी के दो दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 262-159 वोटों से इस व्यापक प्रतिबंध विधेयक को पारित किया था।
- अगर ट्रंप भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाते हैं तो भारत पर कुल अमेरिकन टैरिफ 110 प्रतिशत हो जाएगा। ज्ञातव्य है कि अमेरिका “फोर्ब्स लेबर” से बने सामान के आयात को रोकने के लिए 10 प्रतिशत टैरिफ पहले ही लगा चुका है।
- नए कानून के तहत रूस के सामान पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है।
- इस कानून के तहत जिन देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है, उनमें भारत व चीन के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किए, सिंगापुर, अज़रबैजान, हंगरी, किर्गिस्तान, स्लोवाकिया व कजाखिस्तान शामिल हैं।

इस कानून का उद्देश्य उन वित्तीय संसाधनों को कम करना है, जो यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को जारी रखने में मदद करते हैं। यह कानून रूसी अधिकारियों, बैंकों, ऊर्जा क्षेत्र और मोस्को के सैन्य अधिकारियों का समर्थन करने वाली विदेशी संस्थाओं को निशाना बनाता है। यह कानून ट्रंप को रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार देता है,

ताकि उनकी रूसी तेल और गैस पर निर्भरता कम की जा सके।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वेज एंड मीस कमिटी के अनुसार, इस कानून में रूसी वस्तुओं पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इसमें उन देशों से आने वाली वस्तुओं पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का भी प्रावधान है, जो रूस से तेल और गैस खरीदने से जुड़े प्रावधानों के दायरे में

स्पष्ट रूप से शामिल करने की मांग की गई थी, ताकि ये देश बिल के सैंकेडरी टैरिफ प्रावधानों के तहत 100 प्रतिशत तक टैरिफ के दायरे में आ सकें।
हालांकि, यह संशोधन अपने आप में भारत पर 100 प्रतिशत ड्यूटी नहीं लगाता है।
अगर ट्रंप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, तो भारत पर यह टैरिफ लगाया जा सकता है।
अगर ट्रंप भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाते हैं, तो यह उस 10 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त होगा, जो अमेरिका फिलहाल नई दिल्ली से होने वाले आयात पर लगाता है। यह टैरिफ जबनर मजदूरी (फोर्ब्स लेबर) से बने सामान के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर जुर्माने के तौर पर लगाया गया है।
हालांकि, नए टैरिफ का भारतीय निर्यात पर वास्तविक असर तभी आंका जा सकेगा, जब अमेरिका टैरिफ की दरों की घोषणा करेगा। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

इंदिरा गांधी इन्टरनैशनल एयरपोर्ट पर तीसरा रनवे शुरू

दिल्ली, 19 सितंबर। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का तीसरा रनवे (11A/अ/29एल) रविवार से विमानों के परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके लिए

- इससे यात्रियों को उड़ानों में देरी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

सभी आवश्यक निरीक्षण, परीक्षण और नियामकीय मंजूरियां प्राप्त हो चुकी हैं। इस रनवे के पुनर्वास का कार्य फरवरी 2026 में शुरू किया गया था। इस दौरान रनवे को अधिक मजबूत बनाने के साथ-साथ सुरक्षा, परिचालन क्षमता और भविष्य की सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण के कार्य किए गए हैं।
रनवे के दोबारा शुरू होने से एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक सुचारु होगी और परिचालन दक्षता में भी उल्लेखनीय (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर, 19 सितंबर। जयपुर नगर निगम के महापौर चुनाव को लेकर कई दिनों से चल रही सियासी हलचल शनिवार को नामांकन के आखिरी दिन एक नए मोड़ पर पहुंच गई। भाजपा ने तमाम मंथन और पार्षदों की रायशुमारी के बाद आखिरकार वार्ड 112 के पार्षद और पूर्व जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी को अपना प्रत्याशी बनाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने आखिरी समय तक चले मंथन के बाद वार्ड 118 की पार्षद सुनीता महावर को मैदान में उतारा। दोनों पक्षों के नामांकन के साथ महापौर चुनाव की राजनीतिक तस्वीर सामने आ गई। हालांकि, कांग्रेस की ओर से सुनीता मेठी और दशरथ अटल के नाम से भी नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनकी स्थिति नामांकन पत्रों की जांच के बाद साफ होगी।
150 सदस्यीय नगर निगम में भाजपा के 78, कांग्रेस के 57 और

अन्य पार्षदों में निर्दलीय तथा एआईएमआईएम का एक पार्षद शामिल है। हालिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस की संख्या 57 हुई है। भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा है, जबकि कांग्रेस ने बहुमत से कम संख्या के बावजूद प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को चुनावी रूप दिया है।
भाजपा ने महापौर प्रत्याशी के चयन को लेकर अंतिम समय तक पते नहीं खोले। शुक्रवार को पार्टी ने अपने पार्षदों से पसंद के तीन-तीन नाम लिए और इसके बाद पार्षदों को पुष्कर के होटल में रखा गया। पार्टी के भीतर सुनील कोठारी के अलावा पुनीत कर्णावट, विमल अग्रवाल, शैलेंद्र भार्गव और अन्य नामों को लेकर चर्चा चलती रही। शनिवार को नामांकन का समय नजदीक आने के साथ भाजपा पर नामांकन दाखिल कराया गया। उनके साथ सांसद मंजू शर्मा, विधायक



प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी ने करीब 1:44 बजे कोठारी के नाम की आधिकारिक घोषणा की। इसके बाद कोठारी को जयपुर लाया गया और पार्टी नेताओं की मौजूदगी में निगम मुख्यालय पर नामांकन दाखिल कराया गया। उनके साथ सांसद मंजू शर्मा, विधायक

- जयपुर महापौर पद के एक अन्य दावेदार, पुनीत कर्णावट, सुनील कोठारी के नामांकन के दौरान साथ नज़र आए।
- भाजपा के मुकाबले कम पार्षद होने के बावजूद कांग्रेस ने सुनीता महावर का नामांकन महापौर के लिए भरवाया।

कालीचरण सराफ, बालमुकुंद आचार्य, पूर्व महापौर अशोक लाहोटी, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल सहित कई नेता और पार्षद मौजूद थे।
भाजपा में महापौर पद के लिए कोठारी के साथ-साथ पूर्व उपमहापौर पुनीत कर्णावट सहित कई नामों पर चर्चा थी। कर्णावट भी प्रमुख दावेदारों में बताए जा रहे थे। कोठारी के नाम की घोषणा के बाद कर्णावट उनके साथ नामांकन के दौरान नज़र आए और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का

मलाल नहीं है तथा वे कोठारी के साथ हैं।
नामांकन दाखिल करने के बाद सुनील कोठारी मोती डूंगरी गणेश मंदिर गए और दर्शन किए। इससे पहले उन्होंने निगम परिसर में स्थित गणेश प्रतिमा के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ लगी रही। समर्थकों ने कोठारी के समर्थन में नारे लगाए।
कोठारी ने नामांकन के बाद पार्टी नेतृत्व और जयपुर की जनता का आभार

जताते हुए कहा कि शहर की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने के लिए वे हरसंभव प्रयास करेंगे।
भाजपा के पास 78 पार्षद होने के बावजूद पार्टी नेताओं ने निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा करते हुए 100 से ज्यादा वोट मिलने की बात कही। विधायक कालीचरण सराफ ने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ लोग भाजपा के संपर्क में हैं और क्रॉस वोटिंग हो सकती है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी भाजपा के कुछ पार्षदों के संपर्क में होने का दावा किया गया है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि मेयर चुनाव में पार्टी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। दोनों दलों के इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यानी संख्या के स्तर पर दोनों दलों की स्थिति अलग है, लेकिन मतदान तक पार्षदों की वास्तविक रणनीति और मतदान का रुख सामने नहीं आएगा।

चार हाईकोर्ट्स में 14 जजों की नियुक्ति

नई दिल्ली, 19 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने दिल्ली समेत चार हाई कोर्ट में शनिवार को 14 जजों को नियुक्त किया।
कानून मंत्रालय की अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, दिल्ली हाई

- दिल्ली हाईकोर्ट में सर्वाधिक दो जज व 5 अतिरिक्त जज नियुक्त किए गए हैं।

कोर्ट में दो जज और पांच अतिरिक्त जज नियुक्त किए गए हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में एक जज नियुक्त किया गया है।
झारखंड हाई कोर्ट में तीन जजों और कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की गई है। न्यायिक अधिकारी और वरिष्ठ वकील 5 को हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया जाता है। अतिरिक्त जजों की नियुक्ति आमतौर पर दो वर्षों के लिए की जाती है, जिसके बाद अतिरिक्त जजों को स्थायी जज के रूप में पदोन्नत किया जाता है।